बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

मंगलवार, तिथि ११ दिसम्बर, १९६२।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में मंगलवार, तिथि ११ दिसम्बर, १९६२ को पूर्वाह्न ९.३० बजे अध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण सुधांशु के सभापतित्व में हुआ।

राजकीय संकल्प।
OFFICIAL RESOLUTION.

चीनी आक्रमण की निन्दा एवं मुठभेड़ में मृत बहादुर जवानों के प्रति श्रद्धांजलि।
CONDEMNATION OF THE CHINESE AGGRESSION AND HOMAGE PAID TO THE JAWANS WHO FELL IN THE BATTLE FIELD.

अध्यक्ष—श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह दो मिनट में अपना वक्तव्य समाप्त करें।

---

*श्री मनीश्वर प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं कल आपके माध्यम से सदन से यह कह रहा था कि देश की आजादी कायम रखने के लिये पहली पंक्ति में हमारे जवान लड़ रहे हैं, दूसरी पंक्ति होमगार्ड और नेशनल कैडेट कोर (N. C. C.) का है जो युद्ध करने के लिये तैयार हो रहे हैं। तीसरी पंक्ति एयर रेड प्रिकौशन और वालंटियर फोर्स का है। इसके बाद वर्कर की पंक्ति है जो एयरफिल्ड और इसी तरह के दूसरे उपयोगी चीजों के कनस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं। इसके बाद लैंड आर्मी को भी तैयार करने की आवश्यकता है जो देश की पैदावार को बढ़ावे। अभी हम बाहर से करीब ४५ लाख टन अन्न मंगाते हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि इस जगह पर अन्न की इतनी पैदावार बढ़ायी जाय कि हमारे देश में ही ९० लाख टन अन्न पैदा हो जाय जिसमें बाहर से अन्न मंगाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाय। अगर इस तरह से हो तो इससे हमारी मोरालिटी बढ़ जायेगी। इसके अलावे रूरल वालंटियर फोर्स और भिलेज डिफेंस फोर्स भी कायम करना है जिसमें गांवों में अमनचैन कायम रहे और जवानों को मोर्चे पर हर सामान ठीक समय पर पहुंचता रहे। इसके अलावे गांव-गांव में एक भिजिलेन्स कमिटी की भी स्थापना होनी चाहिये जो रोजमर्रे की चीजों पर ध्यान रखे और उनका दाम नहीं बढ़ने दे। फिर इन सभी को कोआर्डिनेट करने के लिये भी एक कमिटी बननी चाहिये। इसके बाद फिर मैं यह कहना चाहता हूं कि २६ जनवरी को हर साल हमलोग स्वतंत्रता-दिवस मनाते हैं। इस बार जब हम २६ जनवरी को

स्वतंत्रता-दिवस मनावें तो हमलोगों को फिर से इसकी प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि हमलोग अपने देश को स्वतंत्र रखने के लिये हर तरह की कुर्बानी करने के लिये तैयार हैं। इसके अलावे हर विधायक को भी अपने-अपने क्षेत्र में उस दिन मुक्ति-दिवस मनाना चाहिये और फिर लोगों से उस दिन एक-एक रुपया सुरक्षा कोष में दान देने के लिये कहना चाहिये । इसी तरह से हर एक मिनिस्टर को भी अपने कंस्टिच्युएन्सी में जाना चाहिये और वहां पर भी मुक्ति-दिवस मना कर फिर वहां के लोगों से एक-एक रुपया सुरक्षा कोष में दान देने के लिये अनुरोध करना चाहिये और इस तरह से हमारा ख्याल है कि करोड़ों रुपया आसानी से जमा हो जायगा ।

अध्यक्ष—बम्बई में जिस तरह से किया गया है, क्या उसी तरह से आप भी चाहते हैं ?

श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह—जी हां, इसलिये हम यह चाहते हैं कि अगली २६ जनवरी को 'भिक्टरी डे' मनावें और उस दिन हम एक-एक रुपया लोगों से दान लेकर करोड़ों रुपया सुरक्षा कोष में जमा करने की कोशिश करें । ऐसा आसानी से हो सकता है यदि हमलोगों में लगन और तत्परता हो । इस स्टेट में भी ४ करोड़ इस तरह से जमा हो सकता है । इतना ही कहकर मैं यह कह देना चाहता हूं कि अगर हमलोग लगन और तत्परता से काम करेंगे तो अवश्य विजयी होंगे ।

*श्री रफीक आलम—जनाब सदर, माननीय चीफ मिनिस्टर की ओर से जो प्रस्ताव सभा के सामने लाया गया है उसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं। अभी सदन के अन्दर सभी पार्टियों की तरफ से यह कहा गया है कि वे पार्टी पोलिटिक्स और दलबन्दी को भूल कर मुल्क को सही सलामत रखने के लिये एकमत हैं और अभी जो मुल्क पर खतरा आया है उसका मुकाबला करने के लिये तैयार हैं। अभी मुल्क पर जो खतरा आया हुआ है उसमें हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख और इसाई की बात को भूल कर सब लोगों को आपस में मिल कर मुल्क को बाहरी आक्रमण से बचाने में लगना चाहिये ।

हम इस वक्त हिन्दू हैं न मुसलिम हैं, न सिक्ख न इसाई,
अगर कुछ हैं तो हैं इस देश इस धरती के सौदाई,
इसी को जिन्दगी देंगे, इसी में जिन्दगी पाई,
लहू के रंग से लिखा हुआ एक रंग हो जाओ ।।

आज नेफा और लद्दाख के शहीद जवानों की खून का तकाजा है कि हम सभी लोग मिल-जुल काम करें और अपने मुल्क को आजाद रखें। आज जो हमको आजादी मिली है तो हमारे मौलाना मजहरुल हक और आजाद की कुर्बानी से मिली है, हमारे सुभाष चन्द्र बोस की कुर्बानी से मिली है और खुदा का शुक्र है कि हमारे पंडित नेहरू की कुर्बानी की वजह से मिली है और आज वे जिन्दा हैं और फिर हमारी आजादी को कायम रखने के लिये लड़ रहे हैं। अभी हमलोगों को उनके हाथ को मजबूत करना है क्योंकि अभी एक बहुत ही नाजुक वक्त आया हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, यह लड़ाई सीमा की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई डेमोक्रेसी और इन्टरनेशनल कम्युनिज्म की है। जब चीन ने देखा कि उसके यहां सोशल डिजोर्डर है, उसकी तरक्की नहीं हो रही है और हिन्दुस्तान की तरक्की दुगुनी-तिगुनी हो रही है चाहे वह ऐग्रीकल्चरल फिल्ड में हो, चाहे इन्डस्ट्रीज में या कल्चरल आसपेक्ट में हो तो उससे नहीं रहा गया और उसने हिन्दुस्तान पर हमला कर दिया। हमने कल तक चीन को भाई कह कर पुकारा था, जिसको हमने साथ-साथ बैठाया था, जिसको हमने भाई कह कर सीने से लगाया था, जिसकी गर्दन में फूलों का हार पहनाया था आज उसी गर्दन के लिये हमको तलवार बन जाना है। मैं दो तीन सुझाव आपके सामने पेश करना चाहता हूं। पहला सुझाव मेरा यह है कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जैसे पूर्णियां, सहरसा और दरभंगा में कम्युनिकेशन को ठीक किया जाय जिससे मिलिटरी के मूवमेंट में रुकावट पैदा न हो। पूर्णियां में किशुनगंज से पूर्णियां भाया बहादुरगंज तक एक सड़क बनवा दिया जाय। मौजावारी घाट में महानन्दा पुल बनवा दिया जाय और इस काम को वार फुटिंग पर किया जाय। दूसरा सुझाव यह है कि इस युद्ध काल में एकोनोमी भी करना चाहिये। इसके लिये आवश्यक यह है कि ऐसे समय में चाहे लेजिस्लेटर्स हों या मिनिस्टर हों या आफिसर्स हों, टी० ए० नहीं मांगें। तीसरा सुझाव मेरा यह है कि गांवों के लिये विलेज डिफेन्स फोर्स बनाया जाय। इतना ही कहकर मैं बैठ जाता हूं।

*श्री युवराज—अध्यक्ष महोदय, कई दिनों से चीन द्वारा किये गये आक्रमण सम्बन्धी प्रस्ताव पर वाद-विवाद चल रहा है। मैं माननीय सदस्य श्री रामानन्द तिवारी के संशोधन के सम्बन्ध में अपनी राय जाहिर करना चाहता हूं। आज चीन के हमले से पूरे देश तथा एशियाई, अफ्रीकी आदि पड़ोसी देशों में आतंक फैल गया है। आज ऐसा लगता है कि यहां के चाहे वे गरीब हों या अमीर हों, बूढ़े या जवान हों सभी को एक परे-शानी बढ़ गयी है और सभी यह सोचने लगे हैं कि आज देश पर खतरा है। जिस आजादी को हासिल करने के लिये हमने लाखों की कुरबानियां की, एक नयी परम्परा की स्थापना की लेकिन चीन के हमले से ऐसा लगता है कि हमारे जीने का जो ढंग है यानी लोकतंत्रीय प्रणाली उस पर खतरा हो गया है। यह प्रश्न सीमा विवाद का नहीं है। अगर सीमा विवाद का प्रश्न होता तो जिस तरह से चीन ने नेपाल और बर्मा के साथ सीमा विवाद को सुलझा लिया और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लिया वह इसी तरीके से भारत के साथ भी सुलझा सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। १९५६ में जिस पंचशील को चीन ने मान लिया था अगर वह उसी को मानता तो हमारे और चीन के बीच जो समस्या थी उसका निवटारा हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनकी विस्तारवादी नीति, उनकी प्रसारवादी नीति है। उन्होंने जो आक्रमण किया है उससे दुनियां की शांति भंग हो गयी है। परन्तु मैं आपसे निवेदन कर यह कह देना चाहता हूं कि चीन ने जो किया है उसे अपना फल भोगना पड़ेगा। हिटलर और मुसोलोनी की नीति भी विस्तारवादी की नीति थी और दुनियां में राज्य करना चाहते थे। पहले वह आगे बढ़ता गया, परन्तु आप जानते हैं बाद में उसे पीछे हटना पड़ा। यह ठीक है कि न्याय के पक्ष में जीत होती है और अगर यह सत्य है तो चीन को पछताना पड़ेगा। अगर चीन को एशिया पर हुकूमत करने की मंशा है और दुनियां में अगर यह सच्चाई है कि सत्य की बिजय होती है तो चीन को इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। हमें घबड़ाने की जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, त्रिपुरा में प्रकाशित होने वाला केरल क्रोनिकल नामक अंग्रेजी पत्र है और वह कम्युनिस्ट पार्टी का पत्र है, वह कम्युनिस्ट पार्टी की देन है। उसमें एक

समाचार छपा था जिसका विरोध कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा नहीं निकला। अध्यक्ष महोदय, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा पेकिंग का समर्थन प्रकाशित हो और उसका विरोध नहीं निकले इससे क्या साबित होता है यह समझने की बात है। इसके बाद श्री ज्योति बसु का स्टेटमेंट निकला और यह स्टेटमेंट अखबार से मिलता-जुलता था। उनका कहना था कि चीन का जो थ्री प्वायन्ट्स प्रोपोजल है उसे मान कर शांतिपूर्वक समझौता किया जाय। अध्यक्ष महोदय, बाद में कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से इस स्टेटमेंट को बदला गया। लेकिन यह सोचने की बात है कि भारतीय कम्युनिस्ट की क्या नीति है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह जो चीन ने नीति अख्तियार की है वह बड़ा ही खतरनाक है। मैं इस सिलसिले में और भी आपके सामने अपनी राय रखता परन्तु समय की कमी है। इसलिये मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश पर हमला हुआ है और कल परसों उनकी ओर से जो प्रस्ताव रखा गया उससे यह साफ हो गया है कि उन्होंने हमारे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। इससे हमारे ऊपर खतरा और भी पैदा हो गया है। इसलिये मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट और सबडिविजनल हेडक्वार्टर्स के अलावे गांव के आधार पर संगठन होना चाहिये और कम-से-कम एक थाने में एक-हजार होम गार्ड्स की ट्रेनिंग दी जाय।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि हम सिर्फ ओरगेनिजेशन बनाते हैं, काम होता नहीं है। देहात में इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिये और प्रैक्टिस में होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन समय का अभाव है, इसलिये मैं इतना ही कहकर बैठ जाना चाहता हूं कि संकटकालीन के मौके में बीस परसेंट जो स्पेशल ऑफिसर लोगों को स्पेशल पे मिलता है उसे शीघ्र बन्द कर देना चाहिये।

*श्री महम्मद अली जान—जनाबे सदर, कब्ल इसके कि मैं माननीय मुख्य मंत्री के

प्रस्ताव का समर्थन करूं हमारे लिये जरूरी यह हो जाता है कि पहले हम उन वीरों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करूं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिये अपनी जान गंवाई है। मैं खुदा से एवादत करता हूं कि उनकी रूह को और उनके रिश्तेदारों को शांति मिले। हुजूर, मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं कि चीन ने जो हमारे मुल्क पर हमला किया है वह कल हमारे भाई बने हुए थे, हमने उसके साथ भाई का सलूक किया। लेकिन उसने इन्सानियत का काम नहीं किया और हमारे ऊपर हमला कर दिया। अध्यक्ष, महोदय, इस लड़ाई से घबड़ाने की जरूरत नहीं है। कुदरत ने हमें सहायता पहुंचाना शुरू कर दिया है। हम जिस एकता को लाने के लिये उपाय कर रहे थे, हमने देश में एकता पैदा करने के लिये कोशिश की, वह कामयाब नहीं हुई। मगर आज हमलोगों की भावना ऐसी हो गयी है कि लोगों के दिल से गन्दगी साफ हो गयी है। आज हम न हिन्दू हैं, न मुसलमान हैं, न सिक्ख हैं। आज हम सब एक हैं और मातृभूमि के लिये सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हैं। आज हमें कुदरत भी मदद करने को तैयार है।

दूसरी बात मुझे यह कहना है कि आज हमारे जो भाई सत्य और अहिंसा के नाम पर लड़ाई से हिचकिचाते हैं उन्हें भी आज मोर्चे पर जाने से नहीं हिचकिचाना चाहिये। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का प्रचार किया लेकिन यह सत्य और अहिंसा का

फार्मूला हैवान के लिये नहीं है। उनका मुकाबला सत्य और अहिंसा से नहीं किया जा सकता है। उनके लिये तो गोली और तलवार की जरूरत है। इसलिये मैं कहता हूं कि आज जो हिन्दुस्तान में सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं उन्हें भी आज हैवानों को सजा देने के लिये गोली और पिस्तौल से मुकाबला करना चाहिये।

एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि आज लड़ाई के सामानों के इन्तजाम करने की जरूरत है न कि जरूरत इस बात की है कि जो लोग हमारे साथ हैं उनकी नुक्ताचीनी करें। हमें यह देखना है कि लड़ाई में किन-किन चीजों की जरूरत है। लड़ाई के लिये हमें लड़ने का सामान चाहिये, रास्ता चाहिये और रसद का सामान चाहिये। आज की परिस्थिति में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज सबसे ज्यादा रास्ते की जरूरत है और रास्ते का इन्तजाम होना चाहिये और खास कर उन जिलों में जो सरहद पर पड़ते हैं और जहां पर ज्यादा खतरा महसूस करते हैं, वहां पर की सड़कें जल्द-से-जल्द बनवाई जायें।

हमलोगों को काफी तायदाद में फौजों को तैयार करना है। इसके लिये हमें इन्तजाम करना है। जैसा पहले बोलने वालों ने कहा है इसके लिये जिला स्तर पर इन्तजाम किया जाय तो अच्छा है। आज हम अपने इलाके से नवजवानों को लड़ाई में भर्त्ती होने के लिये भेजते हैं तो उनकी भर्ती में बड़ी दिक्कत होती है। इससे अच्छा यह होता कि एक-एक मिनिस्टर, या डिप्टी मिनिस्टर या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी एक-एक जिला के इन्चार्ज बन जायें और वे ही एक-एक जिला का इन्तजाम करें। आज फौज में भर्त्ती की हालत यह है कि इसमें बड़ी दिक्कत उपस्थित होती है। अगर मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर इन्चार्ज रहेंगे तो इसमें दिक्कत नहीं होगी और काम में सहूलियत पैदा होगी।

रास्ते की सहूलियत के बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सिलीगुड़ी तक जाने के लिये एक रास्ता है। उनका एप्रोच रोड अच्छी तरह से दुरुस्त नहीं हो सका है, वह रास्ता कुछ लम्बा है। लेकिन दूसरा रास्ता काढ़ागोला से दार्जिलिंग होते हुए सिलीगुड़ी जाता है। लेकिन एक रास्ता कसबा से होकर है जिसमें आधा खर्च होगा। इस रास्ते को तैयार करने से हम लड़ाई का सामान आसानी से पहुंचा सकते हैं और लड़ाई में काफी कामयाबी हासिल कर सकते हैं।

*श्री जीनबी० मुंजनी—अध्यक्ष महोदय, चीनी आक्रमण के संबंध में जो प्रस्ताव

रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। चीन को हमलोगों पर चढ़ाई करने का हिम्मत इसलिये बढ़ा कि पहले उसने तिब्बत और जापान पर चढ़ाई की थी। उसका मन बढ़ा हुआ था ही और उस पर भी कम्युनिस्ट लोगों ने खबर दे दिया। यह चढ़ाई आज नहीं शुरू हुई, वह तो तीन वर्ष पहले ही हमलोगों के घर में घुस गया था, हमारे नेताओं की लापरवाही से किसी ने उसे रोकने का यत्न तक नहीं किया। वह तो १९५९ में ही घुस गया और आज हमलोगों को शिक्षा दे रहा है कि हमलोग आजाद हुए तो आजादी में राज्य चलाने के लिये कौन-कौन चीजों की जरूरत है। हैदराबाद निजाम हिन्दुस्तान में आ गया इससे वहां का रेजिमेंट हमलोगों के अन्दर आ गया, बिहार रेजिमेंट हमलोगों का हुआ लेकिन इसके अलावे भी हमलोगों को और सेना रखना चाहिये था। सिपाही बहुत जरूरी चीज है राज्य के चलाने के लिये। जब अंग्रेजों का राज्य था तो हमलोग निहत्थे थे, उस वक्त हमलोग कुदार, फाल से लड़ लिया करते थे लेकिन अब हमलोगों को राज्य चलाने के लिये सेना का बढ़ाना बहुत जरूरी है। कुछ सदस्यों ने सजेस्ट किया था कि गांवों में वॉलंटियर्स फोर्स या जिस तरह का भी

हो वॉलेंटियर तैयार करना चाहिये और उनलोगों को बराबर लड़ने के लिये तैयार रहना चाहिये। यह बहुत जरूरी काम है चूंकि अब देश हमारा आज़ाद है, हमलोगों को ठेल ढकेल कर भेजा जाय लड़ने के लिये ऐसा विचार नहीं होना चाहिये। ठेल ढकेल कर भेजने का जमाना चला गया। इस तरह की जितनी भी स्कीमें हो सकें करना चाहिये। फालतू-फालतू स्कीमों को बन्द कर देना चाहिये। जैसे हाउसिंग, इससे किसी भी गरीब आदमी को फायदा नहीं हुआ है, इसके अन्दर किसी गरीब आदमी का मकान नहीं बना है, केवल ट्रेजरी बेंच पर बैठे लोग अपने लिये मकानों का भरमार कर रहे हैं। गरीबों के नाम पर वे बिजनेस करते हैं।

उसके बाद कर्ज की बात आती है। बड़े-बड़े लोगों से क्यों नहीं कर्ज की वसूली करते हैं, केवल गरीबों पर सर्टिफिकेट लागू करके वसूल करते हैं। हम गरीब तो अपना तन, मन, धन, सोना, चांदी, लड़का वगैरह सब कुछ देने को तैयार हैं। रूलिंग पार्टी के कामों को गौर करके देखा जाय तो मालूम होगा कि कितने शर्म की बात है ये सब। आज जात-पात का झगड़ा खत्म हो गया लेकिन तब भी चन्दा वसूलने की बात होती है तो कहा जाता है कि बी० डी० ओ० वसूल करेगा, सी० ओ० वसूल करेगा, हमलोग जो लाखों आदमियों के रिप्रेजेन्टेटिव हैं वे सब ऐरू-गैरू हो गये, हमलोगों पर विश्वास ही नहीं है, यह सब क्या है? यह सब केवल अपना-अपना नाम बढ़ाने के लिये किया गया है। मैं कहूंगा कि थाने-थाने में जो जमा होता है उसे जिले में जमा कर देना चाहिये।

कोई आदमी अपना नाम कमाने के लिये ऐसा कर रहा है, कोई चाहता है कि स्वयं हम प्रधान मंत्री के पास रुपये भेजें और कोई चाहता है कि राष्ट्रपति के पास भेजें। अगर ऐसा जो लोग कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो इसका हिसाब-किताब लगाने में कठिनाई होगी और देरी भी होगी। इसलिये मैं कह कहना चाहता हूं कि अपने थाने में इसके लिये रुपया जमा किया जाये और इसे एक जगह जमा करके जिलावार एक जगह भेजा जाय तो अच्छा होगा। चाहे कोई सोना दे, चांदी दे या मोती दे, यह सब तो ठीक है, लेकिन हमने जो सुझाव दिया है उस पर अमल किया जाय। सिर्फ आंकड़ा दिखलाने से काम नहीं चलता है, १५ मन सोना जमा हुआ है, यह कहने से काम नहीं चलेगा। हमारे देश में सोना है लेकिन हमलोग भीखमंगी कर रहे हैं, दूसरे देश के लोग हंसते हैं कि हमलोग भीख मांग करके पैसा जमा कर रहे हैं। ऐसा करने से पता चलता है कि हमारा खज़ाना सोना चांदी से घट गया है। इन सब बातों के अलावे हमलोगों में एकता होनी चाहिये जिसकी हमलोगों में और इस देश में बहुत कमी है।

अध्यक्ष—अब आप समाप्त कीजिये।

श्री जौन बी० मुंजनी—अच्छी बात है। हमारा लड़का वार में है, चीन में है, फ्रांस में है, हमलोग क्या करते हैं जिसको आपलोग अच्छी तरह से जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि सेना में बहाल होने के लिये उसका अच्छी तरह से सरकार की ओर से इन्तजाम किया जाय। कौन आदमी लड़ाई में जाने के काबिल है उस पर ध्यान दिया जाय। जो लोग पहाड़ में रहते हैं, उनलोगों को सबसे पहले सेना में लिया जाय। एन० सी० सी० की ट्रेनिंग स्कूल में लड़कों को दी जाती है, यह तो ठीक है लेकिन

कौन इसके लायक है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आज हमारे आदमी नेफा में हैं, लद्दाख में हैं और हर जगह में है। सेना में बहाल होने के समय कहा जाता है कि घूस दोगे तो बहाल करेंगे, इस सरकार को ध्यान देना है।

*श्री अवध बिहारी दीक्षित—अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री का जो प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत

है उसका हृदय से मैं स्वागत करता हूं। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसपर हम सभी लोगों को गम्भीरतापूर्वक विचार करना है। विरोधी पार्टी के कुछ लोगों ने इसकी आलोचनायें भी की हैं, प्रिप्रेयर्डनेस, अनप्रिपेयर्डनेस, एलायनमेंट और ननएलायनमेंट की बातें कही गयी हैं। हमारे ख्याल में संकटकालीन स्थिति में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिये। खैर, हर पार्टी का दृष्टिकोण अलग-अलग होता है। यह समय नहीं है कि उन बातों की चर्चा की जाय और उन पर कीचड़ उछाला जाय। मैं समझता हूं कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिये। हमने जो भाषण सुना है उसपर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उनलोगों की सीमा जो है या दायरा जो है वे उससे आगे निकलना नहीं चाहते हैं। खैर, जो हो, चीन ने आक्रमण किया है और पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्टेटमेंट से पता चलता है कि यह सीमा की लड़ाई नहीं है बल्कि आइडियोलौजी (Ideology) की लड़ाई है। चीन यह चाहता है कि भारत जो तटस्थ की नीति बरत रहा है वह न बरते, वे चाहते हैं कि युद्ध की आशंका बनी रहे लेकिन भारत नहीं चाहता है। लेकिन भारत की नीति स्पष्ट है। भारत की अपनी शांति की नीति है और उसी नीति को लेकर वह आगे बढ़ना चाहता है और आगे बढ़ भी रहा है और इसी के चलते आज भारत सम्मान और ख्याति को प्राप्त कर रहा है। आज दुनिया में स्थाई रूप से युद्ध नहीं हो सकती है। भारत मानव का कल्याण चाहता है। यही कारण है कि यह इतना आगे बढ़ चुका है और बढ़ रहा है। लड़ाई बहुत दिनों तक चलने वाली है इसलिये हमको इस पर ध्यान देना है। दुनिया में उसी की विजय होती है जो सत्य पर चलता है और मानव का कल्याण चाहता है। भारत की अवश्य विजय होगी और चीन को एक-एक इन्च भूमि छोड़कर जाना पड़ेगा। इसमें कोई चिन्ता की बात नहीं होनी चाहिये। आखिर हमलोगों का कर्त्तव्य क्या है? कुछ माननीय सदस्यों ने यह सवाल उठाया है कि मंत्रियों की संख्या कम होनी चाहिये और उनका वेतन भी कम होना चाहिये और मंत्रियों को सिर्फ ५०० रुपया लेना चाहिये। ऐसी जो बातें हो रही है वह सिर्फ भावना से प्रेरित होकर हो रही है। आज जो स्थिति है उसमें सरकार चाहे तो सारी चीजों को ले ले सकती है लेकिन वैसा नहीं कर रही है। लोग अपने ही मन से धन और जन दे रहे हैं और देने को तैयार हैं। इसलिये मैं सदस्यों से अर्ज करूंगा कि आज हमारा सूबा कन्स्टीचुएन्सी में बंटी हुई है और हरएक सदस्य को अपने-अपने कन्सटीचुएन्सी में जाना चाहिये और यदि लोगों से एक-एक रुपया लिया जाय तो हरेक महीने में साढ़े चार करोड़ रुपया आ सकता है और साथ ही साथ लोगों से सम्पर्क भी कायम रहेगा। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ जो माननीय मुख्य मंत्री का प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री सैमुएल मुन्डा—अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री ने चीन के हमला के संबंध में जो

प्रस्ताव पेश किया है उसको मैं व्यक्तिगत रूप से और झारखंड पार्टी की ओर से समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, जब हमारे मुख्य मंत्री प्रस्ताव पेश कर रहे थे मैं उस समय यह सोच रहा था कि हमारे सरकार को इस प्रस्ताव को बहुत आगे पेश करना चाहिये था।

(एक सदस्य बोलते हुए सदस्य के बीच से आकर अपना स्थान ग्रहण किया।)

अध्यक्ष—शांति,शांति । इस ढंग से सदन में आना गलत तरीका है।

श्री सैमुएल मुन्डा—विहार के लोग तेजपुर और डिवरूगढ़ में पड़े हुए हैं। आज विहार सरकार को चाहिये था कि इस स्थिति में हमारी सरकार की ओर से, मंत्रिमंडल की ओर से जिसमें आज एक आदिवासी मिनिस्टर भी हैं, आदिवासियों को एक सुसंवाद भेजा जाता। सरकार को चाहिये था कि किसी मंत्री को या सदन के कुछ सदस्यों को भेजकर वहां की जनता में उत्साह लाते। आज १५ वर्षों से मैं यह देख रहा हूं कि जब से आजादी मिली हमारी सरकार इसी में लगी रही कि प्रान्तों की सीमा कैसे बने और बहुत से प्रान्तों की सीमायें बदल भी गयीं। लेकिन यह हमलोगों ने कभी नहीं सोचा कि हमारे देश की सीमा भी बदल सकती है। आज हमें यह सोचना है कि इस परिस्थिति की हम कैसे मुकावला करें। हमारे इलाके के जो नवजवान वहां लड़ रहे हैं उनके प्रति हम क्या कर रहे हैं ? उनके लिये यह कोई नई बात नहीं है। हमारे आदिवासी जवान जब कभी लड़ाई चलती रही है उसमें भाग लेकर अपनी वीरता का परिचय देते रहे हैं। जापान में लड़ाई हुई तो हमारे आदिवासी नवजवानों ने अपना जीवन दान किया। मैं यह इसलिये कहता हूं कि मैं यह साबित करना चाहता हूं कि हम आदिवासी किसी से भी देश की रक्षा करने में पीछे नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत सी बड़ी-बड़ी बातें कही गयीं हैं। बड़ी-बड़ी बातों से काम नहीं होता। जो बड़ी बातें करते हैं वे कुछ करते नहीं हैं। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि आसाम के क्षेत्र में जहां हमारे भाई हैं उनके वीच में जाकर सरकार की ओर से कोई मंत्री या सदस्यों का दल जाकर उनमें उत्साह लावें। जब हमारे नवजवान मिलिटरी में भर्त्ती होने के लिये जाते हैं तो उनको अनफिट कर दिया जाता है। कम-से-कम बीसों जवान रांची में हतोत्साह होकर मेरे सामने रिक्रूटिंग ऑफिस से लौटे। उनका कहना था कि जब हम भर्त्ती होने के लिये जाते हैं तो हमसे कहा जाता है कि तुम अनफिट हो और जब हम लाचार होकर हटिया में काम करने जाते हैं तो हमको काम भी नहीं दिया जाता है। भूख से परीशान होकर वे भर्त्ती होने के लिये जाते हैं लेकिन न उन्हें भर्त्ती किया जाता है और न उन्हें हटिया में काम ही दिया जाता है। मेरा कहना है कि हम किसी से पीछे नहीं हैं, हमको भी देश की सेवा करने का मौका दिया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार का ध्यान इस ओर लाना चाहता हूं कि हमारे नवजवानों को देश सेवा का मौका दिया जाय।

अध्यक्ष—अब सरकार का जवाब होगा।

श्री विनोदानन्द झा—अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि सभी माननीय सदस्यों को अपने विचार रखने का मौका नहीं मिला। यदि सभी माननीय सदस्यों को विचार प्रकट करने का मौका मिलता तो निस्सन्देह सरकार को और सहायता मिलती उनके नये-नये सुझावों से। आखिर कोई काम करने के लिये समय की पावन्दी रहती है और उसी के अनुसार काम होता है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जब कभी आगामी सत्र में सुविधा मिलेगी तो उन्हें इस विषय पर वाद-विवाद करने का मौका मिलेगा।

अध्यक्ष—यदि लड़ाई चलती रहेगी तब।

श्री विनोदानन्द झा—आपने बात ठीक ही कही। लेकिन यह हमारी चिन्तन की दुर्बलता है और हम यह सोचें कि लड़ाई नहीं चलेगी। जितने उपादान और लक्षण लड़ाई के हैं वे इस ओर ले जा रहे हैं कि लड़ाई चलेगी। इस तरह हमें जरा भी नहीं हिचकिचाना चाहिये और चीन की विस्तारवादी नीति का मुकबला करने के लिये तैयार रहना है। अभी यह लड़ाई रुक गयी है लेकिन दस वर्ष के बाद हो सकता है कि भीषण रूप धारण कर ले। इसलिये जबतक चीनी अपनी तलवार को म्यान में न घुसालें तबतक हिन्दुस्तान का कल्याण नहीं हो सकता है। यह संकट का बादल उस समय आया जब हमारे बीच नेहरू, विनोबा और राजेन्द्र बाबू हैं। इनका नाम मैं इसलिये लेता हूं क्योंकि वे गांधी जी के अनुयायी हैं और जब हिन्दुस्तान में क्रांति चल रही थी तो उस समय इन तीनों का विचार त्रिवेणी के ऐसा होता था। इसलिये अभी जो संकट आया है या जो संघर्ष का सामना करना पड़ा है वह दो, चार वर्षों के लिये ही नहीं है बल्कि यह संघर्ष बराबर के लिये है। लेकिन इसका अन्त होना जरूरी है। हमलोग शांतिप्रिय हैं लेकिन चीन का रुख हमसे उलटा है और जिसके बारे में रात ही पंडित जवाहर लाल नेहरू ने रेडियो पर संदेश देते हुए कहा है कि यदि लड़ाई चलती रहेगी तो उस समय हमारा रुख क्या होना चाहिये। जो प्रस्ताव हमने सदन के सामने रखा है उसपर माननीय सदस्यों ने जो संशोधन के जरिये उसके शब्दावली में परिवर्त्तन करना चाहा है उसको पढ़ने के बाद मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता हूं। जहांतक मूल प्रस्ताव का संबंध है उसमें "पिपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना" शब्द हैं। मैं मानता हूं कि मेरे सामने दो ही रास्ता है, या तो अंग्रेजी में जो शब्द रखा है "रिपब्लिक आफ़ चाइना" रखें या जो उसका हिन्दी में अनुवाद है उसको रखें क्योंकि चीनी सरकार का प्रस्ताव में लाना हर तरह से जरूरी है। लड़ाई के बाद हम कंपनसेशन का दावा करेंगे।

हम कम्पेन्सेशन किससे मांगेंगे, कौन देगा? केन्द्र में यानी लोक सभा में जो प्रस्ताव पास हुआ है उसकी शब्दावली भी ऐसी ही है और बंगाल विधान मंडल से जो प्रस्ताव पास हुए हैं उसमें भी वही शब्दावली है यानी 'पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना'। साथ ही आजतक जितने पत्राचार हुए हैं उसमें भी 'पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना' ही लिखा रहता है। इसलिये "चीन की सरकार" कर देते हैं। शब्द 'पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना' में बड़ा ही द्वन्द्वाभाष है। पीपुल्स को तो कहां फेंक दिया गया है उसका पता भी नहीं है। यह तो उसी तरह से है जिस तरह से कोई अपने लड़के का नाम "पद्मलोचन शर्मा" रख दे। मैं सदन के भावनाओं का आदर करता हूं। अतः जो सुझाव हमलोग केन्द्र को देंगे उसमें शब्द "जनतंत्र चीन की लोकतांत्रिक सरकार" के बदले शब्द "चीन की सरकार" दे दूंगा।

तिवारी जी का जो संशोधन है वह सारपूर्ण है और उसको मैं ले लेना चाहता हूं और उसके अनुसार प्रस्ताव में यह जोड़ दिया जाता है कि:

"अन्त में यह सदन बिहार की जनता को राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों और पंचमांगियों और मुनाफाखोरों से सावधान करता है और आशा करता है कि जनता स्वयं भी ऐसे तत्वों पर चौकसी रखेगी।"

जिस स्थिति में आज हम हैं उसमें मूल्य वृद्धि या मुनाफाखोरी बहुत ही खराब है। इसपर सबसे पहले जनता को ही सावधान रहना है और सबसे पहले जनता ही चौकसी करेगी। यह सुझाव भी सराहनीय है। इसलिये इस हिस्से को भी हम अपने प्रस्ताव में जोड़ देना चाहते हैं। इस तरह से प्रस्ताव जिस रूप में संशोधित होकर सदन से पास होगा वही में भेजूंगा। इसके बाद और कई बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहां बहस के दौरान में लायी गयी है, इसमें कुछ बातें आवश्यक भी हैं और बहुत सी बातें ऐसी हैं। जहां हमारी लाचारी है जैसे रिक्रूटमेंट में कमी या वेशी आदि इन सब बातों में हमलोग आदेश नहीं दे सकते हैं लेकिन इन सब बातों का उल्लेख करके सुझाव में मिनिस्ट्री में भेज दूंगा कि हमारे सदन में इस-इस तरह की राय दी गयी है और आशा करता हूं कि आप इन सब बातों पर ख्याल करेंगे। हमारे पास आदमी का खान है। काफी तायदाद में स्वस्थ, बहादुर और लड़ाकू आदमी हम दे सकते हैं। अब रही खर्च में कमी करने की बात, यह बहुत ही जरूरी है। यदि आज लड़ाई नहीं भी रहती तो हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है जिसमें खर्च में कटौती करना जरूरी होता। आपको याद होगा कि मैंने इस वर्ष भी घाटे का ही ही बजट पेश किया था। हमारी आमदनी बढ़ाने के जितने भी स्त्रोत थे वे सब आजकल बन्द हो गये हैं। आमदनी बढ़ाने के लिये जो-जो विधेयक प्रस्तुत होनेवाले थे सदन के सदस्यों और पार्टी के इच्छानुकूल उसको हमने स्थगित कर दिया है। खासकर इस इमर्जेन्सी में तो यह निहायत ही जरूरी है। अभी तक आप लोगों ने जो मदद किया है उसके लिये धन्यवाद देता हूं। राजस्व मंत्री और वित्त मंत्री २३ तारीख को एक कान्फ्रेंस इसी विषय पर करने जा रहे हैं। इसके बाद भी जो आप लोगों का सुझाव होगा किया जायगा। आज जो सवाल उपस्थित है वह पार्टी का सवाल नहीं है बल्कि देश के जीने-मरने का सवाल है, इसलिये जो मदद देना चाहते हैं उसका फैसला आपको करना है। आप जो फैसला करेंगे उसका हम ईमानदारी से पालन करेंगे। तत्कालीन बजट में कटौती करना अनिवार्य है।

फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जिन मामलों में कटौती का आदेश दिया है वे ये तीन विषयों से संबंधित हैं :—

(*a*) Reduction of expenditure on other items.

(*b*) Reorientation of the State Plan.

(*c*) Sanctions for Civil Defence and allied expenditure.

यह नया खर्च है जो देश की सुरक्षा के लिये अनिवार्य है। इसके बाद और जो खर्च में कमी करने के लिये आदेश हैं वे इस प्रकार हैं :

(1) Except in unavoidable circumstances, no new posts are to be sanctioned. Even where new posts are sanctioned, attempt should be made to surrender posts of equivalent emoluments.

जहां तक संभव हो सके कोई नया पोस्ट नहीं सैंक्शन किया जायगा। अगर किसी विभाग को कोई पोस्ट के लिये बहुत जरूरत हो तो उसको नया पोस्ट देने के लिये उस विभाग का पुराना पोस्ट जो उसको दिया गया है इक्वीवैलेन्ट वैलू का पोस्ट सरेन्डर करना होगा।

(2) As far as possible all vacant posts are being left unfilled. At the Block level vacancies of the following categories are being

left unfilled: Animal Husbandry Extension Supervisor, Junior Statistical Supervisor, Lady Health Visitor, Social Education Organiser, Panchayat Supervisor, Co-operative Supervisor, Sanitary Inspector, Industries Supervisor, Field Co-operative Supervisor.

(3) 10 per cent reduction has been made in the provision under Travelling Allowance. Journeys by Government plane have been restricted to 2 per day. No T.A. by own car is being allowed for journeys between places connected by rail.

(4) No officer is being sent to any conference outside the State. The holding of seminars and conferences is being discouraged. The State Government will not participate in any exhibition. No study tours are being allowed.

(5) Strictest economy is being exercised in the declaration of any visitor as State guest. Free transport to State guests has been limited to a radius of 10 miles from the first point of start. Parties at Government cost has been stopped.

(6) Purchase of new furniture is not being allowed. Special restrictions have been imposed on repairs and polishing of old furniture.

(7) Limits of expenditure on telephone bills of Ministers, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries have been fixed.

टेलीफोन बिल के संबंध में इस तरह का सीलिंग है कि उससे बेशी का बिल नहीं दिया जायगा।

(8) Use of telegrams has been limited. Strictest scrutiny is being exercised in the use of service postage stamps.

(9) 50 per cent of the expenditure on repairs of buildings is being saved. No outside colour washing is allowed. Gravelling or tarring of approach roads has been postponed. Special repairs and quinquennial repairs are being kept in abeyance.

(10) All new construction of buildings has been stopped except where necessary for strengthening the economic base of the Defence and Civil Defence requirements.

एनुअल रिपेयर जो रूटीन के मुताबिक किया जाता था उसको बन्द कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस संबंध के जितने सरकुलर्स परिचारित हुए हैं उनकी एक-एक कॉपी में टेबुल पर रख देना चाहता हूं।

श्री कपिलदेव सिंह—अगर उसकी एक-एक प्रति हमलोगों को भी दी जाती तो

ज्यादा अच्छा होता।

श्री विनोदानन्द झा—ठीक है इन सब सरकुलरों की एक-एक कॉपी माननीय सदस्यों के पते पर भेज देने के लिये व्यवस्था कर दी जायगी।

All new constructions have been stopped.

नये मकान बनाने का काम वन्द कर दिया गया है और इसमें प्राथमिक स्कूल के भवन से लेकर सेक्रेटेरियट की इमारत बनाने का काम बन्द कर दिया गया है। इसी तरह से जीप और स्टाफ कार खरीदना भी वन्द कर दिया गया है। अभी जितने जीप और स्टाफ कार हैं इतने हैं कि उनमें से कुछ को निकाल कर सिविल डिफेन्स के काम में दिया जा सकता है। आज जितने जीप ब्लौक में हैं, वहां के डाक्टरों के चार्ज में हैं, या इसी तरह से दूसरे विभाग में हैं। उनमें एक अच्छा हिस्सा सिविल डिफेन्स के काम के लिये निकाला जा सकता है।

No new jeeps or other types of motor vehicles are being allowed to be purchased. A list of available motor vehicles has been prepared and requirements of Civil Defence, etc., will be met from that list.

इसी तरह से पोस्ट में भी कमी करने की बात है।

Detailed scrutiny of sanctioned posts in the Secretariat and attached offices has been made. Personnel required for Civil Defence and other purposes will be made available from the surplus that emerges as a result of the above scrutiny.

हरेक विभाग में पोस्ट को कम करने के सवाल पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अलावे एयर रेड से बचने के लिये ट्रेन्चेज खोदने की आवश्यकता है और इसके लिये भी अफसर की आवश्यकता है। लेकिन अभी सरकार इस काम के लिये कोई अलग से बहाली नहीं करना चाहती है बल्कि जो हमारे पास सरप्लस अफसर हैं उनसे ही काम लेने का इंतजाम किया जा रहा है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—इस तरह से इकोनोमी करने से कितने रुपये का बचाव होगा ?

श्री विनोदानन्द झा—इसे तो हम फरवरी के अंत में ही बतला सकते हैं। अभी तो प्लैन को भी कम किया जा रहा है और जहां इस साल में प्लैन पर ६३ करोड़ रुपया खर्च करने की बात थी वहां पर अभी ५८ करोड़ खर्च करने की बात है। अगले साल के प्लैन से भी कटौती हो रही है और ६९ करोड़ की जगह ५० करोड़ रुपया खर्च करने की बात सोची जा रही है। इस तरह से जहां तक हो सके खर्च को कम करने की कोशिश हो रही है। छोटे-छोटे मामलों में खर्च कम करने की बात है। लेकिन इसके अलावे कहीं-कहीं पर खर्च को बढ़ाना भी होगा।

श्री कामदेव प्रसाद सिंह—जिनका वेतन १ हजार रुपया से ज्यादा है उनके वेतन में किसी तरह की कटौती की बात है या नहीं ?

श्री विनोदानन्द झा—जिनका वेतन १ हजार रुपया से ज्यादा है वे केन्द्रीय सरकार के सर्वेन्ट हैं और केन्द्रीय सरकार की मर्जी के बिना उनके वेतन से किसी प्रकार की कटौती नहीं हो सकती है।

श्री कपिलदेव सिंह—मिनिस्ट्री में किसी प्रकार की कटौती होने की बात है या नहीं?

श्री विनोदानन्द झा—इसका जवाब हम पीछे देंगे। अभी कैबिनेट वार कैबिनेट की तरह काम कर रही है।

पी०डब्लू०डी० की ओर से वही काम हो रहा है जिनकी जरूरत लड़ाई को ठीक तरह से चालू रखने से है और डिफेंस के लिये नयी-नयी सड़कें भी बनायी जानेवाली हैं।

श्री मुन्द्रिका सिंह—सिविल डिफेन्स के लिये एक मिनिस्टर रखने की जरूरत होगी?

श्री विनोदानन्द झा—इसके लिये मिनिस्ट्री की संख्या में वृद्धि करने की जरूरत पड़ सकती है। हमने तीन बटालियन ५१ लाख रुपये के खर्च पर मिलिटरी पुलिस के लिये मंजूरी दी है। ६० कंपनी आर्म्ड होमगार्ड पर भी २१ लाख रुपये खर्च करने के लिये मंजूरी दी गयी है। दो हजार एडीशनल रूरल होमगार्ड के लिये भी १४ लाख और रुपये खर्च करने के लिये मंजूरी दी गयी है।

गांवों में सिविल डिफेंस का ट्रेनिंग देने के लिए २० लाख रक्षा दल कायम करने का हमने स्कीम बनाया है। जैसा कि इस तरह का स्कीम बम्बई वगैरह में है वही हमारे यहां के लिए भी संगत है। अगर हम गांवों में स्टैचुटरी या रेगलर फोर्स बनावें तो यह डुप्लीकेट हो जायगा क्योंकि हम गांवों के लिए वॉलन्टियर फोर्स बना ही चुके हैं। अगर दोनों फोर्स हम बनाते हैं तो इन दोनों में काम का वितरण करने में कठिनाई होगी। हम ग्राम रक्षा दल को विस्तृत करना चाहते हैं और २० लाख लोगों को ही ट्रेनिंग देना चाहते हैं। इसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ४० लाख रुपया सैन्कसन किया है। इसमें एडीशनल कौस्ट भी हो सकता है। फिर भी अभी यह बहुत कम एमाउन्ट है। अभी पटना में एक ही फायर यूनिट है जो बहुत ही कम है। हम चाहते हैं कि १० यूनिट और बढ़ावें तो इतने यूनिट से हमारा काम चल सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि पटना में फायर ब्रिगेड की वृद्धि की जाय। जहां तक कटौती का सवाल है, जहां तक संभव हो सकता है वहां तक हम कटौती कर रहे हैं। उत्पादन की दिशा में हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में सुनने के लिए सदस्यों की इच्छा है और इच्छा ही नहीं है बल्कि उनमें उद्वेग भी है। कृषि में ५० प्रतिशत उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम स्कीम बना रहे हैं। फल और सब्जी का उत्पादन प्रचुर मात्रा में हो इसके लिए १४४ ब्लौक्स चुने गए हैं खास करके इंडस्ट्रियल एरिया में क्योंकि वहां आसानी होगी। केन्द्र से जो आदेश आया

है उस आदेश को सामने रखते हुए पूर्णिया और सहरसा जिले में ३०० एकड़ आलू की और २ हजार एकड़ प्याज की खेती करने का प्रबन्ध कर रहे हैं। वहां इस चीज की खेती इसलिए कर रहे हैं कि वहां सामान भेजने में आसानी होगी। लड़ाई के जमाने में खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक नया पैटर्न अख्तियार करना होगा और तभी जाकर उत्पादन में वृद्धि होगी। वह परिस्थिति अब आ गयी है कि हम उस पैटर्न को सामने रख कर काम करें। इन्हीं सब बातों को सोच कर हमने शाहाबाद जिले में इन्टेन्सिव पैकेज प्रोग्राम बनाया जिससे कि उत्पादन में लगभग डबली की वृद्धि हो जाय। इसी तरह से राइस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट में भी इस चीज को विस्तार करने की बात है। पौलट्री और फिशरी के लिए भी प्रोग्राम बनाया जा रहा है और इसलिए कि अगर एक शाम चावल न मिले तो मछली खाकर ही लोग रह सकें। हमें गांवों की तरफ भी ख्याल ले जाना है। हमें इसके लिए बहुत चिन्ता थी कि गांवों में जूट और मेज का दाम गिरे। हमें खुशी है कि आज मकई का दाम कुछ गिरा है। लेकिन जूट उपयुक्त मूल्य में अभी नहीं मिल रहा है। कृषि मंत्री ने हमें बतलाया है कि जूट के लिए एक मार्केटिंग यूनियन होगी जिसके द्वारा जूट की कीमत उचित मूल्य पर रखी जायगी। मेज का ही नहीं दूसरी चीजों की भी कीमत घट रही है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण यह है कि या तो सोने का मूल्य घटना या अधिक उत्पादन बढ़ना या तीसरा यह हो सकता है कि चूकि किसानों से अपील की जा रही है कि वे बकाये रुपये सरकार को दे दें तो इसके लिए किसान जल्दीबाजी में अपने गल्ले को निकाल कर बेच रहे हों। जो भी हो, सरकार गल्ले की कीमत के सम्बन्ध में बहुत जल्द ही उचित कीमत के लिए फैसला कर देगी। यदि ऐसा मालूम हो कि कोई अनुचित ढंग से अधिक दाम लेकर गल्ला बेच रहा है और देश में संकटमय स्थिति पैदा होने की संभावना है तो हम प्राइस सपोर्ट की नीति काम में लायेंगे और दाम बढ़ने नहीं देंगे। यदि सोने के भाव को भी स्थिर रखने की जरूरत समझेंगे तो उसके लिए भी प्राइस सपोर्ट की नीति काम में लायेंगे ताकि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने नहीं पावे। इसलिए गल्ले के भाव में और सोने के भाव में सामंजस्य स्थापित रहना चाहिए। इसकी पूरी कोशिश की जायगी।

श्री कामदेव प्रसाद सिंह—किरासन तेल, ऊल, और नारियल तेल आदि के दाम जो बढ़ रहे हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं?

श्री विनोदानन्द झा—किरासन तेल वगैरह की कीमत तभी बढ़ सकती है जब उसका आना बन्द हो जाय या कम परिमाण में आवे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। किरासन तेल की कमी नहीं है। हां, यह बात सही है जैसा कि कल माननीय सदस्य ने कहा कि नेपाल के बोर्डर पर लोग किरासन तेल की चोरी करते हैं। मैं इसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करता कि चोरी नहीं होती है। लगभग २५, २६ लाख रुपये का किरासन तेल नेपाल जाता था लेकिन इधर ५८ लाख रुपये का तेल नेपाल चला गया। हमने केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि नेपाल में इतना अधिक तेल जा रहा है, वह क्या उसके माध्यम से कहीं बाहर तो नहीं जा रहा है? क्योंकि नेपाल वाले इतना अधिक तेल पीयेंगे तो नहीं? तो इसपर केन्द्रीय

सरकार की ओर से हमें आश्वासन आया और खुशी इस बात की है कि केन्द्रीय सरकार इस संबंध में उचित व्यवस्था कर रही है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि किरासन तेल का दाम नहीं बढ़े या जहां कहीं लिकेज होता हो तो इसके लिए लोकल डिफेन्स कमिटी है, लोकल प्लानिंग बडी है या जो भी कमिटी हो, उसको देखना है कि अगर कोई इस काम में हाथ बढ़ाता है, किसी को ऐसा करने में हिस्सेदार बनाता है तो उसपर कड़ी कारंवाई की जाय। आपको देखना है कि अगर कोई आदमी जो यहां भी व्यापार करता है और नेपाल में भी व्यापार करता है और यहां जयहिन्द लिखता है और नेपाल में जय नेपाल लिखता है और रात में इस तरह का माल चोरी से पार कर देता है तो उसपर आपको कड़ी नजर रखनी चाहिए। जो चोरी करता हुआ पकड़ा जाय तो उसका नाम ब्लैक लिस्ट में दर्ज कर लिया जाय। उसको सरकार किसी तरह की सुविधा नहीं देगी।

श्री रामानन्द तिवारी—उसको जेल भेजा जायगा या नहीं?

श्री विनोदानन्द झा—जेल भेजा जायगा। जहां लोकल आॅर्गेनाइजेशन काम नहीं करती है वहां तो जेल जाना अनिवार्य है।

श्री रामानन्द सिंह—प्रोसीक्यूशन के लिए आपके पास कानून है?

श्री विनोदानन्द झा—हमारे पास सभी कानून है। सभी कानून इंफोर्स हो जायेंगे। सबसे सुप्रीम कानून है डिफेन्स आॅफ इंडिया ऐक्ट, जिसके जरिये यदि कोई भी आदमी कानून का उल्लंघन करता है या ऐसा कोई काम करता है जो सरकार की नजर में, देश की हित में अच्छा नहीं है तो उसके लिये यह डिफेन्स आॅफ इंडिया ऐक्ट कायम है और उसके चलते कम-से-कम ६ महीने तक तो उसको जरूर जेल भेजा जा सकता है। तो मैं कह रहा था कि उद्योग के मामले उत्पादन की वृद्धि में किसी तरह की कमी नहीं हो, इसके लिए केन्द्रीय श्रम मंत्री ने एक त्रिदलीय सम्मेलन दिल्ली में बुलाया था। त्रिदलीय सम्मेलन का नतीजा यह हुआ कि एक इंडस्ट्रीयल ट्रूस बनी जिसकी मानी यह होती है कि कोई भी यूनियन इस इमरजेन्सी में हड़ताल वगैरह नहीं कर सकती जिससे प्रोडक्शन में बाधा हो। इसकी होने की संभावना भी नहीं है। माननीय सदस्य या गैर-सरकारी यंत्र को यदि इस तरह की चीज मालूम हो तो वे लेबर डिपार्टमेंट को खबर दे देंगे और त्रिदलीय सम्मेलन के फैसले के अनुसार इस चीज को रोका जायगा। परन्तु मेरा विश्वास है कि इस तरह की चीज होने की संभावना नहीं है।

दूसरी चीज यह हुई कि जितने प्रकार के उत्पादन में वृद्धि हो सकती है उसे किया जाय।

तीसरी चीज यह हुई कि मजदूर वेजेज ऐक्ट में संशोधन करके एक दिन की मजदूरी लेने की चेष्टा की जायगी। बिहार राज्य के लेबर डिपार्टमेंट ने अपने प्रदेश में, जितने मिल मालिक और उद्योगपति थे, मजदूर यूनियन के प्रतिनिधि थे

उन लोगों का एक सम्मेलन किया। छोटानागपुर डिवीजन में घूम-घूम कर जहां-जहां उत्पादन बढ़ सकती थी उसकी एक लिस्ट बनाई गयी, इंडस्ट्रीयल हारमोनी कायम रखने के लिए एक कमिटी बनाई गयी।

श्री रामानन्द तिवारी—मजदूर वेजेज ऐक्ट में संशोधन करके एक दिन की मजदूरी लेने की बात है, तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि मिल मालिकों से लेने की बात है या नहीं जिसमें समान रूप से, रेशियो के अनुपात में उनसे लिया जाय।

श्री विनोदानन्द झा—वे भी दे रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं यह बतला देना चाहता हूं कि धनबाद के एक श्री अर्जुन प्रसाद ने एक दिन की आमदनी देने का तय किया और ग्यारह हजार दिया भी। बाटा कंपनी है और अन्यान्य सेक्टर्स हैं वे ऐच्छिक अनुदान दे ही रहे हैं। फिर इंकम टैक्स, सुपर टैक्स है जो मजदूरों के साथ नहीं है।

श्री रामानन्द तिवारी—पूरे दिन की आमदनी मालिक देंगे या नहीं मैं यह जानना चाहता हूं?

श्री विनोदानन्द झा—ग्यारह हजार के हिसाब से एक दिन की आमदनी इमरजेन्सी पीरियड में वे देंगे।

श्री रामानन्द तिवारी—जो मुनाफा होगा वही न देंगे?

श्री विनोदानन्द झा—हां।

श्री राम नारायण शर्मा—११ हजार देने की बात नहीं है। १,१०० देने की बात थी। १२,००० रुपया दस दिनों की आमदनी दी गयी है।

श्री विनोदानन्द झा—ठीक है। सिंहभूम और धनबाद जिले में ऐसा हुआ है। दोनों एक दूसरे से लेने-देने के मामले में टप जाना चाहते हैं।

तो मैं कह रहा था कि कमिटी जो बनी है वह डिफरेन्ट डिपार्टमेंट से लिस्ट मांग कर देख रही है कि आवश्यकतानुसार जिन चीजों की जरूरत हैं उन चीजों की उत्पादन में वृद्धि हो। महायंत्र हो या छोटा यंत्र हो सभी उत्पादन बढ़ायेंगे, कोई भी बैठे नहीं रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, हमने काफी समय सदन का लिया। हम लिस्ट आपके सामने रखते हैं कि क्या-क्या काम हमने किया, किस मार्ग में हम खर्च में क्या कमी कर सके, उद्योग बढ़ाने के लिए क्या रास्ता है, खेती बढ़ाने के लिए क्या रास्ता है, उत्पादन के साथ उचित मूल्य भी मिले यह नहीं हो कि हम उत्पादन बढ़ावें और उसका उचित मूल्य न मिल सके, इसपर भी निगरानी हमें रखनी है, इसके लिए क्या रेमेडी है, यह

भी देखना है। सुरक्षा समिति जो हमने कायम की उसके द्वारा हमने कौन-कौन-सा काम किया वह आपके सामने में रख देना चाहता हूं। आपको और हमको क्या करना है। यह ठीक है कि हमें फौज में भर्त्ती करना नहीं है। लेकिन यह भी ठीक है कि जो काम हमें करना है वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। आज चाईना पाराशूट की ट्रेनिंग दे रहा है। उसकी कल्पना यह है कि जो फौज पहाड़ से उतरे तो हमारी फौज के पीछे पाराट्रूपर को उतारे। यह सबसे बड़ा खतरा है। इस मसले को हम हल करेंगे। हम जिनलोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं यदि राइफल उपलब्ध नहीं हो सके तो हम शार्ट गन भी काफी तैयार कर रहे हैं। मुंगेर में जो कारखाना है बन्दूक का उसके प्रोडक्शन को हम बढ़ा रहे हैं। जो बन्दूक हम तैयार करते हैं उसके लिए इचापुर से सर्टिफिकेट लेने में १२ महीने लग जाते हैं इसको हमने कम करने की कोशिश की है और अब सर्टिफिकेट जल्द मिलेगा। जो बन्दूक हमें इस तरह मिलेगा उसे हम ग्राम सेवा दल को देंगे। सर्वसाधारण को बन्दूक दे देना भी खतरे से खाली नहीं है। इस तरह का जेनेरल आम जनता में बन्दूक दे देना भी खतरे से खाली नहीं है। हमारे पास पंचायत में ग्राम रक्षा सेवक है, जितने फोर्स हम तैयार करेंगे उनको भी हम बन्दूक देंगे।

श्री मंगल प्रसाद यादव—यदि पब्लिक लाइसेन्स लेकर खरीदना चाहे तो मिल सकता है या नहीं?

श्री विनोदानन्द झा—वह तो आर्म्स ऐक्ट के मुताबिक दिया ही जाता है। यह पद्धति जारी रहेगी।

श्री रामानन्द तिवारी—पुलिस वाले ५०० रु० घूस लेते हैं तब देते हैं।

श्री विनोदानन्द झा—सुरक्षा दृष्टिकोण से व्यक्तिगत आदमी को देने में अंकुश रखना जरूरी है। आज हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने बन्दूक लिया और उसको छः महीने में ४०० रु० में बेच दिया और थाने में रिपोर्ट कर दिया कि बन्दूक चोरी हो गई है। आज जिस काम के लिए बन्दूक का उपयोग करेंगे उसके लिए हमें आदमी को तैयार करना है। २० लाख आदमियों को फौजी ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। १ लाख ७२ हजार को राइफल चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जिनको हम बन्दूक की ट्रेनिंग देंगे उन्हें हम बन्दूक देंगे। वे देहातों को आर्म कर सकेंगे। उन्हें समाज के प्रति भी धर्म है और नेशन के प्रति भी धर्म है। दूसरी दिक्कत क्या है उसको भी हाउस से छिपाना नहीं चाहता हूं।

एक और खतरा है कि आफत के समय कम्युनिकेशन गायब हो जायगा, सड़क की बर्बादी होगी, पुल तोड़ दिये जायेंगे, इसके लिए हम अभी पुल पर पहरा दे रहे हैं, नीचे से आकर कोई सबोटेज कर दे इसके लिए हमलोग सचेष्ट हैं लेकिन कहीं ऊपर से आकर टपका दे उसको हम नहीं रोक सकते हैं। बिहार को आसाम से कनेक्ट करने के लिए एक ही रास्ता है यदि वह काट दिया गया तो हमलोगों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए जहां गंगा जी हैं वहां हम नया फेरी सर्विस कर रहे हैं और जहां-जहां एक ही सड़क है वहां दो-तीन सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। बिहार नेशनल हाईवे ३१ को छानबीन करने के बाद उसके लिए ठीका भी दे दिया गया है। और भी एरिया के लिए हमारे पी०डब्लू०डी० मंत्री के यहां स्कीम है, वह स्कीम अभी

हमलोगों के सामने है उसको आपलोगों के बीच सर्कुलेट कर देंगे ताकि उसमें कुछ इजाफा की जरूरत हो तो आप इजाफा उसमें कर सकें। कम्युनिकेशन को अच्छी हालत में रखने के लिए हर हालत से प्रयत्नशील रहना जरूरी है।

इसके बाद दूसरा खतरा है कि यदि गांव में दुश्मन बम गिरा दे तो क्या करेंगे ऐसे तो हमलोग अनुमान करते हैं कि हमारे यहां जो १८ टाउन हैं उन्हीं पर बम गिराया जा सकता है लेकिन हमारे दुश्मन का कोई सिद्धांत नहीं है, वह तो हर वक्त कनफ्युजन क्रियेट करने के लिए ही परेशान रहता है ताकि हमलोग उलझन में पड़ जायें। वह तो बराबर चाहता है कि ऐसा कर दें कि लोगों को रास्ता न मिले, समूचे सड़क पर शरणार्थी पड़े रहें ताकि जोरा फौज आ-जा नहीं सके। तो इसके लिए भी हमलोगों को तैयार रहना चाहिए। यह तैयारी केवल बाहर से नहीं, भीतर से करने की जरूरत है।

मुझे खुशी हुई जब एक सदस्य ने कहा कि हर घर से इसके लिए मदद मिलनी चाहिए। हमारे पास हर घर को संगठित करने की योजना है। हमें प्रत्येक घर से एक-एक लीडर चाहिए, लीडर का मतलब पक्का बालवाला नहीं, एक नवजवान, नवयुवती चाहिए जो अपने घर के लोगों को अपने ऊपर लादकर उन्हें निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा सके। ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दी जायगी, उन्हें बताया जायगा कि जरूरत पड़ने पर किस गांव के लोगों को कहां पर ले जाना होगा। उसके बाद एक वैसा दल होगा जो निर्दिष्ट स्थान पर चटाई, बांस आदि की व्यवस्था करेगा ताकि भागे हुए लोग अपना टेम्पोररी निवास स्थान बना सकें। यह काम निहायत जरूरी है। दूसरे देशों में इस तरह की व्यवस्था की जरूरत नहीं थी चूंकि वहां के नागरिक लड़ाई के तरीकों को जानते हैं पर हमारे यहां उनलोगों से विभिन्नता है, हमारे यहां के नागरिक पिछड़े हुए हैं और लड़ाई उनके जीवन में पहला ही मौका है, यहां के लोगों को लड़ाई का तजुर्बा नहीं है। दूसरे देश में केवल नोटिस छाप कर बांट देने से काम चल जाता है लेकिन यहां ऐसा नहीं हो सकता है। आज एक-एक परिवार को वार के तरीकों से वाकिफ कराना पड़ेगा और एक-एक परिवार को वार फिल्ड से पीरामिड की तरह बना देना पड़ेगा। तीन डीफेंस ब्लौक हैं, वहां भी बातें कर चुका हूं एक जगह बाकी है वहां भी सदन के समाप्त होने पर जायेंगे। इस तरफ सबका ध्यान जाना चाहिए। सबको वार के काम को सम्हालने की कोशिश करनी चाहिए।

इसके बाद हमारे यहां गांवों में रक्षा दल हैं, शहरों में रक्षा दल और होम गार्ड्स हैं उन सबों पर भी भरोसा करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि संकट काल में वे अपनी शक्ति की परीक्षा देंगे और बहुत होशियारी से देखेंगे कि दुश्मन कहीं स्पाई बनकर न आ जायें और आकर पीछे में गड़बड़ कर सकें।

हमारे यहां ग्राम पंचायतों का संगठन भी हो चुका है। आज के पहले भी मौका आने पर उनलोगों ने अपनी परीक्षा दी है। जब कहीं हड़ताल हुआ, कहीं किसी तरह की गड़बड़ी हुई तो वे तुरन्त रेडियो पर सुनते ही काम में लग गये, रेलवे लाईन के किनारे या जहां जरूरत वे समझते थे पहरा देते हुए पाये गये, हमलोगों ने देखा है कि वे बारह बजे रात को, एक बजे रात को और कभी-कभी दो बजे रात को भी पहरा दे रहे हैं। अब तो उनलोगों को तजुर्बा भी हो गया है, इसके बाद हमलोग यहां से प्रेरणा देकर उचित ढंग से खबर देकर कर्त्तव्य परायण उनको बनायेंगे ही।

श्री रामानन्द तिवारी—मिनिस्टरों के वेतन में कटौती करनेवाली बात बाकी ही रह गयी।

श्री विनोदानन्द झा—मैं उसपर भी आ रहा हूं। जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूं वह हमने बताया। डीफेंस कमिश्नर की बहाली हो चुकी, सहायकों की बहाली हो चुकी है, कई अफसरों को चुनकर नागपुर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया है, हर जगह एडवाइजरी डीफेंस कौंसिल का निर्माण हो चुका, महल्ले में वार्डेन की नियुक्ति हो गई। तो महीने दिन के अन्दर पूरी स्कीम डीफेंस के मोतल्लिक फंक्शन कर रही है, रात में ब्लैक आउट करने का रिहर्सल कर रहे हैं और जिस वक्त अग्नि वर्षा हो, अग्नि वर्षा के बाद भी हमलावर यह देख सकें कि बिहार की जनता का मेरुदंड नहीं टूटा है, उसका क्रोध बढ़ता ही जा रहा है, त्याग करने की दिशा में वृद्धि हो रही है।

अध्यक्ष—१० मिनट का समय से काम चल जायगा?

श्री विनोदानन्द झा—जी हां।

श्री राम लखन सिंह यादव—अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन आवर मेम्बर्स आवर है। इसके बाद ही वे बोल सकते हैं।

अध्यक्ष—अध्यक्ष को अधिकार है कि दस मिनट का समय लेकर बोलने दे और बाद में १० मिनट प्रश्न के समय में जोड़ दिया जाय। आप बैठ जायें।

श्री विनोदानन्द झा—हमारी ऐसी धारणा है कि जैसाकि कुछ सदस्यों ने कहा है एकोनोमी का पहला मार्ग है मंत्रियों की तायदाद घटे और कुछ सदस्यों ने कहा कि तन्ख्वाह भी घटा दें। जहांतक तन्ख्वाह घटानेवाली बात है मैं किसी से विरोध नहीं रखता लेकिन मैं जानता हूं कि मंत्री और सदन के सदस्य दोनों एक ही नाव पर हैं, सबों का पहले के कुछ कमिटमेंट हैं। मैं अपने खर्च का ब्योरेवार हिसाब सेंट्रल पालियामेंटरी बोर्ड को हर साल भेज देता हूं और अगर हम या मंत्री या उप-मंत्री या सदस्यों के पास जो हैं यदि उसमें कटौती की जाय तो जो हमारे असहाय कार्यकर्त्ता लोग जिनको मासिक थोड़ा-बहुत दे रहे हैं उसें बन्द करना पड़ेगा। थाना कांग्रेस कमिटी को ५०-५० रु० जो चिराग जलाने के लिए देते हैं उसे बन्द करना पड़ेगा, जिला कांग्रेस कमिटी को जो ५० रु० दे रहे हैं उसे बन्द करना पड़ेगा। उसी तरह के दूसरे लोगों के भी कमिटमेंट्स हैं या हों। सच्ची बात तो यह है कि जब मैं साधारण मंत्री था उस वक्त मझे एक छोटी-सी 'फीएट' गाड़ी थी जिसपर एक गैलन से ३५ मील घूमते थे और २५० ० गाड़ी का एलाउएन्स भी मिलता था लेकिन आज छोटा-सा हवाई जहाज रखना पड़ता है और जिसपर एक गैलन से ९ मील चल पाता हूं। विराट भवन में रहने पर जिसकी बिजली खर्च देने में परेशान रहता हूं, झाड़ देकर साफ रखने के मामले में भी अपनी जगह परेशान रहता हूं। यदि स्थिति उत्तरोत्तर बढ़ती जायगी और हम अपने को

इस लायक नहीं पायेंगे और इसी तरह की आदत डालनी पड़ेगी तो इस तरह से आदमियों के दान करने का सामर्थ्य, बलिदान देने का सामर्थ्य आदि पर विवाद नहीं होना चाहिए। जैसी स्थिति रहेगी उसके अनुसार परिवर्तन होगा और उस वक्त जैसा रिसपौंस होगा लोग करेंगे। मिनिस्टर घटाने के बारे में भी कहा गया। वार कैबिनेट में क्या होता है उस सम्बन्ध में हमने किताबें पढ़ीं। इम्पीरियल डीफेंस कमिटी इंगलैंड में युद्ध के समय बनी और उसके द्वारा जो फैसले होते थे उसे कैबिनेट के सामने महज अप्रूवल के लिए पेश किये जाते। कैबिनेट में भी एक ऐसी कमिटी बना दी गई जो हमसे अलग है और उसके निर्णय की मान्यता देनी पड़ती है और तब उसके बाद कौंसिल ऑफ वार बना और वार कैबिनेट बना। दोनों के मानी यह नहीं है कि मौजदा जो कैबिनेट है वह बन्द हो जाता है। वार कैबिनेट के आदमी विदाउट पोर्टफोलियो है जो सिर्फ युद्ध के सम्बन्ध में चिंता कर सके। दोनों समय मीटिंग हो ताकि हमसे रिपोर्ट प्राप्त होती रहे।

एक माननीय सदस्य—यह तो केन्द्रीय सरकार की बात है लेकिन प्रांतीय सरकार से तो सम्बन्धित नहीं है।

श्री विनोदानन्द झा—प्रांतीय सरकार के जिम्मे भी काम है और एक-एक कदम मिलाकर केन्द्र के साथ चलना है। एक किताब है "सर आइवर जेनिंग्स का कैबिनेट गवर्नमेंट" जिसके कुछ शब्द मैं सुना देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है:

"The experience of the war taught several lessons. First, the ordinary Cabinet system provides insufficient control where day-to-day decisions of outstanding importance have to be taken. The Cabinet system assumes that the main lines of departmental policy can be laid down well in advance, so that the departments can take consequential decisions without constant reference to the Cabinet. Where the pace of national activity has to be speeded up, as in war or in time of financial crisis, the Cabinet system has to be modified.

Secondly, the experience of the War Cabinet shows that, normally, the Cabinet must contain the chief departmental ministers. The conduct of war implies the subordination of governmental activity to the attainment of a single objective. As soon as the demands of the war became less insistent and the demands of peace became obvious, there arose complaints that departmental ministers were deprived of an effective voice in the determination of questions that affected their departments. Evidence to this effect was given before the Machinery of Government Committee in 1918. Also, the matters for determination became wider in their variety and hardly less wide in their

scope. Conflicts between the Prime Minister and the Foreign Secretary (who was not in the War Cabinet) became common. A Cabinet of departmental minister was necessary to control the whole."

इसलिए जहां वार कैबिनेट होता है वहां डिपार्टमेंटल कैबिनेट जो है वह अपनी जगह पर रहता है। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ काम के लोड की कल्पना कर ली जाती है और उसी के अनुसार आदमी मोकर्रर किये जाते हैं। आप इस भयंकर स्थिति की भी कल्पना करते हैं कि मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर की कटौती की जाय। आपको मालूम होगा कि डा० श्रीकृष्ण सिंह जब थे और उनके समय में सन् १९४७-४८ में जो भयंकर कम्युनल रायट हुआ तो उन्होंने हर हिस्से में मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर को बैठा दिया डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में। हमें भागलपुर डिवीजन दिया गया, एक छोटा-सा प्लेन भी दिया गया, जहाज से देखता रहता था और जहां-कहीं आग लगती वहां उतर कर जाता था उसी तरह छोटानागपुर में एक को रखा गया, अनुग्रह बाबू खुद पटने में रहे, महमूद साहब तिरहुत में और इसी तरह क्षेत्रों का बंटवारा किया गया। यदि आज संकटकालीन स्थिति बढ़ती है तो क्या आप चाहेंगे कि मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर सेक्रेटेरियट में ही रहें? आप नहीं पसन्द करेंगे कि मिनिस्टर सहरसा, पूर्णिया में जायें, दरभंगा में बैठें, मुजफ्फरपुर में बैठें, चम्पारण में बैठें? क्यों? इसलिए कि वहां जो तत्काल सरकारी काम हो उसमें किसी प्रकार के वैधानिक विघटन न रहें, वहीं उसकी स्वीकृति मिल जाय कि फलां सड़क बनाओ, पुल टूट गया है, बनाओ, घर जल गया है, बनाओ। कन्स्टीच्युशन तो बदल नहीं जाता है। इसलिए इमर्जेन्सी फूटिंग पर काम कर रहे हैं तो मिनिस्टर को सिर्फ सेक्रेटेरियट लेवेल पर ही नहीं देखना होगा। इमर्जेन्सी के मुकाबले के लिए पावर के साथ कैबिनेट के लोगों को जहां-तहां बैठा दिया जाना आवश्यक है और स्थानीय आवश्यकताओं को देखकर उसकी पूर्त्ति के लिए स्वयं आज्ञा दे दे और बाद में उसकी सूचना यहां दे दें कि हमने यह किया। उसी तरह से सदस्यों को भी वहां बैठना होगा जहां रेलवे स्टेशन तथा पोस्ट आफिस हो। एक तरफ कन्स्टीच्युएन्सी संभालना पड़ेगा और एक तरफ पटना के सिचुयेशन को जानना पड़ेगा और कहां क्या परिवर्त्तन होता है इसे जानना होगा और जब इस तरह से तत्पर होकर सामाजिक परिचर्या करेंगे और संकट समय पर काम कर सकेंगे तो बेड़ा पार होगा। आज निर्माण का अवसर आ गया है, बिहार की जनता ऐसे संकट काल में, पौलिटिकल कनफ्लिक्ट हो या दूसरा कनफ्लिक्ट हो, हम एक होकर किसी तरह से अपने को गिरने नहीं देंगे। (थपथपी।)

अध्यक्ष—माननीय सभानेता स्वयं संशोधित प्रस्ताव उपस्थित करें।

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि जिन्होंने अपना संशोधन दिया है अगर वे अपना संशोधन वापस ले लें और सभा की अनुमति हो तो मूल प्रस्ताव यथा संशोधित सर्वसम्मति से पास हो जाय।

(सभा की अनुमति से सभी प्रस्ताव वापस ले लिये गये।)

श्री रामसेवक सिंह—मैं अपना प्रस्ताव वापस नहीं लूंगा।

अध्यक्ष—अभी आप बैठ जायें।

श्री विनोदानन्द झा—मैं आपके आदेश से निम्नांकित प्रस्ताव उपस्थित करता हूं—

यह सदन चीन की सरकार द्वारा हमारी उत्तरीय सीमा पर किये गये अकारण और नग्न आक्रमण की घोर निन्दा करता है और भारत सरकार को विश्वास दिलाता है कि भारतीय भू-भाग से आक्रमणकारियों को निकाल बाहर करने के लिए भारत सरकार जो भी प्रयत्न करेगी उसमें बिहार की जनता और सरकार का पूर्ण सहयोग प्राप्त रहेगा।

यह सदन उन वीर जवानों के प्रति अपना अन्यतम सम्मान प्रकट करता है जो शत्रुओं को रोक रखने में समर्थ हो सके हैं। साथ ही विस्तारवादी चीन की बहुसंख्यक सेना के साथ भीषण मुठभेड़ में जिन बहादुरों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है उनकी पवित्र स्मृति में यह सदन अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनके शोक-संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक समवेदना प्रकट करता है।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के उद्देश्य की पूर्त्ति के लिए बिहार की जनता ने अबतक धन-जन की जो सहायता प्रदान की है उसकी प्रशंसा करते हुए यह सदन जनता से अपील करता है कि वह केवल वर्त्तमान प्रयत्नों को ही जारी न रखे बल्कि उत्तरोत्तर उन प्रयत्नों को उत्साहपूर्वक अग्रसर करती चले जबतक भारत की पवित्र भूमि से शत्रुओं को बिल्कुल निकाल बाहर नहीं किया जाता।

अन्त में यह सदन बिहार की जनता को राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों और पंचमांगियों और मुनाफाखोरों से सावधान करता है और आशा करता है कि जनता स्वयं भी ऐसे तत्वों पर चौकसी रखेगी।

अध्यक्ष—इस प्रस्ताव पर माननीय सदस्य श्री रामसेवक सिंह का जो संशोधन है उसको वे वापस लेना चाहते हैं ?

श्री रामसेवक सिंह—जी हां, मैं इसको वापस लेना चाहता हूं।

(सभा की अनुमति से संशोधन वापस ले लिया गया।)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन चीन की सरकार द्वारा हमारी उत्तरीय सीमा पर किये गये अकारण और नग्न आक्रमण की घोर निन्दा करता है और भारत सरकार को विश्वास दिलाता है कि भारतीय भू-भाग से आक्रमणकारियों को निकाल बाहर करने के लिये भारत सरकार जो भी प्रयत्न करेगी उसमें बिहार की जनता और सरकार का पूर्ण सहयोग प्राप्त रहेगा।

यह सदन उन वीर जवानों के प्रति अपना अन्यतम सम्मान प्रकट करता है। जो शत्रुओं को रोक रखने में समर्थ हो सके हैं। साथ ही विस्तारवादी चीन की बहुसंख्यक सेना के साथ भीषण मुठभेड़ में जिन बहादुरों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है उनकी पवित्र स्मृति में यह सदन अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनके शोक-संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक समवेदना प्रकट करता है।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के उद्देश्य की पूर्त्ति के लिये बिहार की जनता ने अबतक धन-जन की जो सहायता प्रदान की है उसकी प्रशंसा करते हुए यह सदन जनता से अपील करता है कि वह केवल वर्त्तमान प्रयत्नों को ही जारी न रखे बल्कि उत्तरोत्तर उन प्रयत्नों को उत्साहपूर्वक अग्रसर करती चले जबतक भारत की पवित्र भूमि से शत्रुओं को बिल्कुल निकाल बाहर नहीं किया जाता।

अन्त में यह सदन बिहार की जनता को राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों और पंचमार्गियों और मुनाफाखोरों से सावधान करता है और आशा करता है कि जनता स्वयं भी ऐसे तत्वों पर चौकसी रखेगी।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष—अब प्रश्नोत्तर *का समय हो गया।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

Calling Attention Motion.

जूट के मूल्य का निर्धारण।

FIXATION OF PRICE OF JUTE.

अध्यक्ष—प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हुआ। श्री कपिलदेव सिंह ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की एक सूचना दी है जिसे मैं स्वीकार करता हूं। सरकार वक्तव्य दें।

*श्री बीरचन्द पटेल—जूट मूल्य निर्धारण से भारत सरकार का ही सीधा सम्बन्ध है। यह सही है कि पिछले साल की तुलना में जूट की कीमत गिर गयी है और इससे कुछ असंतोष की भावना भी आ गयी है। किन्तु इसका अर्थ यह लगाना उचित नहीं होगा कि बिहार सरकार ने इस विषय में लापरवाही का परिचय दिया है, जैसा कि माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है। यह ज्ञातव्य है कि बिहार सरकार के निरन्तर प्रयास के कारण ही जूट की कीमतों को स्थिर रखने के लिये भारत सरकार द्वारा प्राइस सपोर्ट की नीति अपनायी गयी थी और भारत सरकार ने आसाम बॉटम किस्म के जूट की न्यूनतम कीमत ३० रु० प्रति मन निर्धारित की है। ऐसी नीति भी थी कि जब इस दर की तुलना में कीमतें गिर जायं तो बफर स्टौक एजेन्सी द्वारा जूट खरीदकर कीमतों को स्थिर रखा जाय।

यह मूल्य निर्धारण कलकत्ते के बाजार में प्रचलित कीमत के आधार पर था, बिहार के प्रायमिक और माध्यमिक बाजारों में नहीं। अतः बिहार के इन बाजारों में जो कीमत ठीक होती है वह कलकत्ते के बाजार की कीमत से भाड़े तथा दूसरे संबंधित खर्चों को निकालकर ही जाना जा सकता है। दुर्भाग्यवश इन कीमतों पर बाजार स्थिर नहीं रह सका क्योंकि बफर स्टौक एजेन्सी ने अपना काम समय पर सुचारू रूप से चालू नहीं किया। अतः राज्य सरकार भारत सरकार का ध्यान इस ओर लगातार आकृष्ट करती रही है। पिछले जून महीने में इस सम्बन्ध में केन्द्रीय कृषि मंत्री डॉ० राम सुभग सिंह से भी विचार विमर्श किया गया। उन्हें यह बताया गया कि कृषकों को जूट की कीमत के गिरने से काफी कष्टों का सामना करना पड़ रहा है और उनसे यह अनुरोध किया गया कि भारत सरकार ऐसी नीति अपनाये कि बॉटम किस्म के जूट की कीमत बिहार के माध्यमिक बाजारों में ३५ रु० प्रति मन हो। केन्द्रीय सरकार ने ३५ रु० की कीमत के संबंध में अपनी सहमति देने में अपनी दिक्कतें बतायी, क्योंकि बिहार के

---

*प्रश्नोत्तर के लिये कार्यवाही (भाग १) देखें।